प्रदान करता है.

नवभारत - 19-11-2024

व्याख्यान

'वैमनिकॉम' में राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के चौथे दिन दिग्गजों ने किया मार्गदर्शन

'सहकारिता' के योगदान पर हो रहा मंथन

■ **पुणे,** नवभारत न्यूज नेटवर्क. सहकारिता प्रबंधन के संदर्भ में प्रशिक्षण दिलाने वाली देश का एकमात्र शिक्षा संस्थान वैकुंठ मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे की ओर से इस समय सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है. 14 नवम्बर को शुरू हुए इस सप्ताह में अब तक सहकारिता क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सहकारिता क्षेत्र के संदर्भ में विस्तार से विचारमंथन हो रहा है. सप्ताह के तीसरे दिन 'सहकारिता : ग्रामीण समृद्धि के लिए बड़ा साधन' विषय पर सहकार भारती के संस्थापक सदस्य सतीश मराठे, विकास अन्वेश फाउंडेशन के वरिष्ठ शोधकर्ता अजित कानिटकर ने मार्गदर्शन दिया.

'सहकारिता : ग्रामीण समृद्धि के लिए बड़ा साधन' पर चर्चा हुई

■ सतीश मराठे ने कहा कि, अगर देश को वाकई में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो इसमें सहकारिता क्षेत्र ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है. उनका विचार था कि सहकारी संस्थाओं को एफपीओ मॉडल के लिए कमर कसनी शुरू कर देनी चाहिए जिससे किसान की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके.

■ इस संदर्भ में वैमनीकॉम जैसी संस्थाएं कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगी. वैमनिकॉम की डाइरेक्टर डॉ. हेमा यादव ने इस समय कहा कि, भारत में डेयरी सहकारी समितियों ने एक लंबा सफर तय किया है और सहकारिता के इस पूरे आंदोलन से डेयरी क्षेत्र में देश के कई किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं.

■ हालांकि, नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ समकालीन और विश्व स्तरीय डेयरी सहकारी इकाइयों की स्थापना के लिए निरंतर कौशल उन्नयन की आवश्यकता है.

'नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा

सहकारिता सप्ताह में चौथे दिन 'नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका' विषय पर मंथन हुआ. इस चर्चासत्र में लोकमान्य मल्टीपर्पज सोसाइटी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुशील जाधव, पाइक्सेरा ग्लोबल के निदेशक यश रंगा ने मार्गदर्शन किया. सुशील जाधव ने कहा कि, बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण सहकारी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. हमारा दृढ़ विश्वास है कि सहकारी समितियां वित्तीय समावेशन और सामाजिक नवाचार के माध्यम से ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा कर सकती हैं. उन्होंने स्टार्ट अप को समर्थन देने के लिए सहकारी समितियों की क्षमता के विचार करने पर जोर दिया.